

मुकदमों का विवरण

नागराज रेड्डी बनाम.

तमिलनाडु राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 886) 21 मार्च, 2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को अपराध के लिए समवर्ती दोषसिद्धि दंडनीय यू/एस एस है। 302, 341 भारतीय दंड संहिता सी. मुख्य रूप से पी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य के आधार पर, एक इच्छुक गवाह, यदि न्यायसंगत ठहराया गया हो।

साक्ष्य-इच्छुक गवाह-पिछली शत्रुता-ऐसी गवाही की पुष्टि के बिना, पूरी तरह से इच्छुक गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि-वैधता:

आयोजित किया गया:पीडब्लू-1 एक इच्छुक गवाह है, जो मृतक का भाई है-उसने स्वीकार किया कि उन पक्षों के बीच पिछली दुश्मनी थी जिसमें मृतक और उसकी पत्नी-पीडब्लू-3 पक्षों के बीच हाथापाई के बाद घायल हो गए थे और उस घटना के संबंध में मुकदमा चल रहा था-पिछली दुश्मनी एक दोधारी तलवार है-एक ओर, यह उद्देश्य प्रदान करता है और दूसरी ओर, गलत निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है-पीडब्लू-1 को निचली न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तों के संबंध में अविश्वसनीय पाया गया था, सिवाय आरोपी Nos.1 और 3-मृतक की पत्नी पीडब्लू-3 सहित अन्य गवाहों ने केवल इतना कहा कि सभी आरोपी व्यक्ति अपने घर आए थे।

457

/

[2023] 14 एस सी आर।

अभियुक्त सं. 3 के विरुद्ध वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से अक्षम्य है-अपीलार्थी की दोषसिद्धि पूरी तरह से पीडब्लू-1 की गवाही पर आधारित नहीं हो सकती थी, बिना पुष्टि के-आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया-अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया-दंड संहिता, 1860-एस। 302, 341.

[पारस 9-13, 15, 16 और 18]

खेमा उर्फ खेम चंद्र आदि। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 एससीसी-ऑनलाइन एससी 991:वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [1957] एससीआर

981 – पर भरोसा किया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 886।

2019 के सी. आर. एल. ए. No.34 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 31.03.2022 से।

रूप:

वेणुगोपाल गौड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिव कृष्णमूर्ति, बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता।
अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., शोभित द्विवेदी, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बी. आर. गवई, जे.

1. यह अपील मद्रास अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की आपराधिक अपील संख्या 34 अंतर्गत पारित 31 मार्च 2022 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिस अंतर्गत उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, होसुर (जिसे इसके बाद 'निचली अदालत' के रूप अंतर्गत संदर्भित किया गया है) द्वारा 2007 की धारा 7 अंतर्गत पारित 20 दिसंबर 2018 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अभियुक्त संख्या 1, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।

459

नागराज रेड्डी बनाम तमिलनाडु राज्य [बी. आर. गवई, जे.] 460

2. नट शेल में अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

2.1. अपीलार्थी सहित अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों के साथ एक राजप्पा (मृतक) कृष्णागिरी जिले के ऊझियालम गाँव का रहने वाला है। यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक और आरोपी व्यक्ति अलग-अलग समुदायों से हैं। राजप्पा की पत्नी राधा (पीडब्लू-3) स्थानीय आउटरीच महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थीं।

2.2. ऊझियालम गाँव में भूमि का एक हिस्सा उपरोक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा खरीदा गया था। उक्त भूमि के चारों ओर एक परिसर की दीवार बनाने के लिए, मृतक के समुदाय के

लोगों को इसके निर्माण का अनुबंध दिया गया था। इस तरह के कृत्य ने दोनों समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा दिया और कई झगड़े हुए, जिनमें से एक के कारण बगलूर पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। दोनों पक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट, होसुर की न्यायालय में अभियोजन का सामना कर रहे थे।

2.3. जबकि स्थिति इस प्रकार थी, राजप्पा 14 सितंबर 2004 को सुबह लगभग 10 बजे अपने बड़े भाई नारायणप्पा (पीडब्लू-1) के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट, होसुर की न्यायालय में गवाही देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर से निकले। न्यायालय जाते समय, आरोपी संख्या 1 से 5 ने उन्हें एक चेक पोस्ट के पास रोक दिया, तुरंत राजप्पा के चेहरे पर मिर्च पाउडर छिड़का और उसकी हत्या कर दी। यह विशेष रूप से आरोप लगाया जाता है कि वर्तमान अपीलार्थी ने राजप्पा पर मिर्च पाउडर फेंका और बाद में राजप्पा के सिर के बाईं ओर प्रहार करने के लिए अपनी दरांती का इस्तेमाल किया। अपराध करने के बाद, सभी आरोपी गाँव वापस चले गए और राजप्पा के घर पर पत्थर फेंके और जोर से घोषणा की कि उन्होंने राजप्पा को मार डाला है, और राजप्पा के परिवार के अन्य सदस्यों का भी यही हाल होगा। इस बीच, नारायणप्पा (पीडब्लू-1), जो घटना स्थल से भाग गया था, वापस गाँव भाग गया और राधा को राजप्पा पर हमले के बारे में सूचित किया। इसके बाद वे अन्य लोगों के साथ घटना स्थल पर लौट आए। इस बीच, कूपलियप्पा का बेटा, जो राजप्पा का भाई है, शिकायत दर्ज कराने के लिए बगलूर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जबकि कूपलियप्पा (पीडब्लू-4) खुद जांच चौकी पर पहुंचा, जहाँ उसने अपने भाई राजप्पा को मृत पाया।

2.4 इसके बाद, पीडब्लू-1 द्वारा राजशेखर (पीडब्लू-11) को दिए गए बयान के आधार पर, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, जिसे शिकायत के रूप में माना गया था, पर 2004 का अपराध संख्या 251 होने का मामला दर्ज किया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

उसी दिन, अर्थात् 14 सितंबर 2004 को दोपहर लगभग 1 बजे, हुडको पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147, 148, 341 और 302 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए, जिसमें अभियुक्त सं. 1-अपीलार्थी नागराजा रेड्डी भी शामिल हैं। जांच अधिकारी (आई. ओ.), मुथामिज मुदलवन (पी. डब्ल्यू.-16) ने एक मजार रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद, राजप्पा के शव की जांच की। इसके बाद राजप्पा के शव को सरकारी अस्पताल, होसुर भेजा गया, जहाँ शव परीक्षण किया गया और मृत्यु का कारण एक महत्वपूर्ण अंग, यानी मस्तिष्क में चोट होना निर्धारित किया गया। इसके बाद आई. ओ. ने आरोपी संख्या 2 से 5 को गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी की तारीख 22 सितंबर 2004 दिखाई गई। अगले ही दिन, यानी 23 सितंबर 2004 को, अपीलार्थी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णागिरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 1 अक्टूबर 2004 को उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

2.5 जाँच के दौरान, आरोपी संख्या 6 से 13 की भूमिका सामने आई और उन्हें भी इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने राजप्पा से छुटकारा पाने की साजिश रची थी, जो उनके समुदाय का एक प्रमुख व्यक्ति था। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ जहां सभी अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताया। अभियुक्त नं. 2, नागी रेड्डी मुकदमे के दौरान मारे गए और इस तरह उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया।

2.6 मुकदमे के समापन पर, निचली विचारण न्यायालय ने अपने 20 दिसंबर 2018 के फैसले और आदेश के माध्यम से आरोपी संख्या 4 से 13 को बरी कर दिया, लेकिन दोषी आरोपी संख्या 1 और 3 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1500/-। निचली विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए काफी हद तक पीडब्लू 1,3 और 4 की गवाही पर भरोसा किया।

3. अभियुक्त संख्या 1 और 3 ने अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उल्लेखनीय है कि राज्य ने 4 से 13 तक अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन श्रीधर रेड्डी, आरोपी संख्या 3 को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि, जबकि उसे घटना के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तारी की तारीख केवल 22 सितंबर 2004 दिखाई गई थी।

4. इसलिए, वर्तमान अपील।

461

नागराज रेड्डी बनाम तमिलनाडु राज्य [बी. आर. गवई, जे.] 462

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वेणुगोपाल गौड़ा और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. को सुना है।

6. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 और 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए घोर गलती की है। उन्होंने कहा कि नारायणप्पा (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के आधार पर आरोपी नंबर 3-श्रीधर रेड्डी को बरी कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, उसी के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि ी रूप से मान्य नहीं है।

7. डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी वर्तमान अपीलार्थी को साक्ष्य की सराहना के आधार पर अपराध का दोषी पाया है। वह प्रस्तुत करता है कि तथ्य के समवर्ती तथ्यों में कोई विकृति नहीं देखी जा सकती है।

8. निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि मुख्य रूप से नारायणप्पा (पीडब्लू-1) के साक्ष्य के आधार पर होती है।

9. नारायणप्पा (पीडब्लू-1) ने अपने साक्ष्य में वर्ष 2002 में आरोपी व्यक्तियों के साथ मृतक की पिछली दुश्मनी के बारे में बताया है, जिसमें मृतक और उसकी पत्नी राधा (पीडब्लू-3) पक्षों के बीच हाथापाई के बाद घायल हो गए थे। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा कि उस घटना के संबंध में मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, होसुर में चल रहा था। पीडब्लू-1 ने आगे कहा कि 14 सितंबर 2004 को लगभग 09 बजे:45 वह और उसका मृत भाई टीवीएस 50 मोटर वाहन पर सवार थे। जब वे एम. एस. नर्सरी फार्म की ओर जा रहे थे, तो आरोपी नंबर 1-नागराजा रेड्डी, आरोपी नंबर 2-नागी रेड्डी, आरोपी नंबर 3-श्रीधर रेड्डी, आरोपी नंबर 4-कृष्णा रेड्डी और आरोपी नंबर 5-रंगनाथ रेड्डी ने उन्हें फसल के चाकू लहराते हुए रोका और फिर उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 1-वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक को फसल के चाकू से वार किया, जिसके कारण मृतक राजप्पा नीचे गिर गया। इसके बाद, आरोपी नंबर 2-नागी रेड्डी ने उसके दाहिने पैर पर काफी बल से फसल के चाकू से हमला किया। नतीजतन, उनका पैर दो हिस्सों में कटा हुआ था। पीडब्लू-1 ने आगे कहा कि, इसके बाद, आरोपी नंबर 3-श्रीधर रेड्डी ने मृतक के बाएं पैर पर हमला किया। उसके बाद, आरोपी नंबर 4-कृष्णा रेड्डी ने उस पर मृतक के सिर के बीच वाले हिस्से में हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह एक छोटे रास्ते से भागे और राजप्पा की पत्नी राधा (पीडब्लू-3) को उक्त घटना के बारे में सूचित किया।

/

[2023] 14 एस सी आर।

10. जहाँ तक अन्य गवाहों का संबंध है, निर्विवाद रूप से उनमें से कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। मृतक की पत्नी राधा (पीडब्लू-3) सहित अन्य गवाहों ने केवल इतना कहा कि सभी आरोपी व्यक्ति गाँव में उनके घर आए और उन्हें प्रोत्साहित किया कि उन्होंने राजप्पा को मार दिया है।

11. एक ही साक्ष्य के आधार पर, आरोपी नंबर 1-वर्तमान अपीलार्थी और आरोपी नंबर 3-श्रीधर रेड्डी को छोड़कर सभी अभियुक्तों को निचली विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी नंबर 3-श्रीधर रेड्डी को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि घटना के कुछ दिनों के भीतर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि गिरफ्तारी 22 सितंबर 2004 को दिखाई गई थी। वर्तमान अपीलार्थी को इस आधार पर दोषी ठहराया गया था कि वह घटना के बाद फरार था और उसने 23 सितंबर 2004 को मजिस्ट्रेट के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था।

12. हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी के मामले को अभियुक्त संख्या 3 के खिलाफ अलग करने में दिया गया तर्क पूरी तरह से अनुचित है।

13. निर्विवाद रूप से, नारायणप्पा (पीडब्लू-1) एक इच्छुक गवाह है, जो मृतक का भाई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी दुश्मनी थी। जैसा कि इस न्यायालय ने खेमा उर्फ खेम चंद्र आदि के मामले में हाल के फैसले सहित कई मामलों में कहा था। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1, पिछली शत्रुता दोधारी तलवार है। एक ओर, यह उद्देश्य प्रदान करता है और दूसरी ओर, गलत निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

14. वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य 2 के मामले में यह न्यायालय

उन्होंने इस प्रकार कहा है: “11. इसलिए, हमारी राय में, यह विधि का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि न्यायालय का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

1 2022 एससीसी-ऑनलाइन एससी 991 2 (1957) एससीआर 981 463

नागराज रेड्डी बनाम तमिलनाडु राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर यह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं है। यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना होगा और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।

15. निर्विवाद रूप से, नारायणप्पा (पीडब्लू-1) को निचली विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 1 और 3 को छोड़कर अन्य अभियुक्तों के संबंध में अविश्वसनीय पाया गया है। जहाँ तक अभियुक्त संख्या 3 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने भी पीडब्लू-1 की गवाही पर अविश्वास किया है।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी सुविचारित राय है कि दोषसिद्धि केवल नारायणप्पा (पीडब्लू-1) की गवाही पर आधारित नहीं हो सकती थी, बिना उनकी गवाही की पुष्टि के।

17. परिणामस्वरूप, अपील की अनुज्ञात जाती है।

18. मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च 2022 को पारित आक्षेपित निर्णय, जिससे निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार किया जाता है, उसके 20 दिसंबर 2018 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। इसमें अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उसे किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात।

दिव्या पांडे